सरकारी कर्मचारियों और कमजोर वर्गों के लिए क्वार्टरों का निर्माण

1647. **श्री आस मोहम्मद :**
चौधरी हर मोहन सिंह :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान सरकारी कर्मचारियों तथा कमजोर वर्गों के लिए कुल कितने क्वार्टर निर्मित किये गये ;

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितने क्वार्टरों का निर्माण किये जाने की संभावना है ;

(ग) इनमें से अब तक कितने क्वार्टर आबंटित कर दिये गये हैं : और

(घ) क्या उपर्युक्त कार्य में कोई विलम्ब हुआ है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के थुंगन) : (क) से (ग) वर्ष 1993-94 के दौरान सामान्य पूल के 2575 क्वार्टर बनाए गए हैं और 1000 क्वार्टरों को चालू वित्त वर्ष 1994-95 के दौरान पूरा किए जाने की सम्भावना है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आवास राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा अपने बजट प्रावधानों से चलायी जाती है। मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस योजना के तहत वर्ष 1993-94 के दौरान 1,22,895 रिहायशी मकान बनाए गए। वर्ष 1994-95 के दौरान 91,990 मकानों का लक्ष्य है जिनमें से 37,999 मकान सितम्बर, 1994 तक पूरे हो गए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विधवाओं के लिए आवास यूनिट

1648. **श्री अनन्तराम जायसवाल :**
श्री सत्य प्रकाश मालवीय :
श्री दिग्विजय सिंह :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वीकृत योजना के अन्तर्गत विधवाओं को रहने के लिए आवास यूनिट उपलब्ध कराने की कोई योजना शुरू की थी ;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब शुरू की गई थी और उस योजना में कितनी विधवा महिलाओं को तत्काल आवास यूनिट देने का लक्ष्य था ;

(ग) क्या इन आवास यूनिटों को उपलब्ध कराने के लिए विधवाओं से कोई धनराशी वसूल की गई थी ;

(घ) यदि हां, तो कब और इस संबंध में कितनी धनराशी ली गयी थी और क्या ऐसी सभी महिलाओं को अब तक आवास यूनिट उपलब्ध करा दिये गये हैं ;

(ङ) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उन्हें आवास यूनिट उपलब्ध कराने के क्या कारण हैं ; और

(च) इस संबंध में दिनांक 15 नवम्बर, 1994 को "दैनिक जागरण" में प्रकाशित समाचार पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) दिनांक 5-11-94 के दैनिक जागरण" में प्रकाशित समाचार बावत वस्तु स्थिति इस प्रकार है :—

700 रुपये तक की मासिक आय वाले महिला-मुखिया परिवारों के लिए एक सहकारी समूह आवास परियोजना बेघरों के लिये घर अन्तर-राष्ट्रीय वर्ग, 1987 के दौरान प्रयोग योजना के रूप में शाहदरा नई दिल्ली में शुरू की गई थी।

एक सहकारी समिति अर्थात स्वयम् सेवा सहकारी आवास समिति, जिसमें 341 सदस्य हैं। सेवा दिल्ली नामक एक स्वयंसेवी संगठन द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण (स्लमविंग) और हुडको के सहयोग से शुरू की गई थी। इसे जहां स्लम विंग ने रियायती दरों पर भूमि आबंटित की वहीं हुडकों द्वारा परियोजना के लिए ऋण सहायता दी गई।

रिहायशी मकानों के लिए धन की व्यवस्था सदस्यों द्वारा अपने संसाधनों से और हुडको से ऋण के माध्यम से की जानी थी ।

यह परियोजना 108.54 लाख रुपये की ऋण वचन बद्धता सहित फरवरी, 1989 में हुडको द्वारा अनुमोदित की गई थी । परियोजना का निर्माण कार्य लाभार्थियों और सोसायटी की प्रबन्ध समिति के बीच विवादों की वजह से कुछ समय के लिये रुक गया था । सोसायटी की प्रबन्ध समिति भंग कर दी गई है और गंजीयक, सहकारी समितियों द्वारा प्रशासक नियुक्त किया गया है । प्रशासक की देख-रेख में निर्माण कार्य पुनः शुरू हो गया है ।

341 मकनों में से 338 का निर्माण कार्य छत स्तर तक पूरा हो गया है और शेष 3 एककों का निर्माण कार्य चल रहा है । परियोजनों की प्रगति के अनुसार हुडको द्वारा अभी तक रिलीज की गई ऋण राशी 93.61 लाख रुपये है । शेष निर्माण और विकास कार्य पूरा करने के लिए सोसायटी ने 79.01 लाख रुपये के अतिरिक्त ऋण के लिए हुडको से निवेदन किया है ।

तथापि, हुडको ने बताया है कि 24-10-94 की स्थिति के अनुसार 11.45 लाख रूपये की हुडको ऋण राशी वापस करने में यह समिति असफल रही है ।

Shifting of Public Sector Units and Governments Offices Out of Delhi

1649. SHRI O.P. KOHLI :
SHRIMATI KAMLA SINHA :
DR. BAPU KALDATE :

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether in 1986 Government had approved the shifting of some Public Sector Units (PSUs) and Government Officers besides other institutions from Delhi to towns of the National Capital Region (NCR) and all the Offices required to be shifted were also identified to remove the congestion of the city;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) how many PSUs/Government Offices and Institutions have actually been shifted to the NCR satellite towns;

(d) what are the reasons for which the otner organisations have not shifted so far; and

(e) what programmes have been drawn up for the shifting of these organisations ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI P.K. THUNGON) (a) and (b) In June, 1988 Government had decided to shifting the offices of 25 Public Sector Undertakings out of Delhi. Subsequently, the office of one Piublic Sector Undertaking, namely Vayudoot was allowed to remain in Delhi. The names of Public Sector Undertakings/Government Offices which are proposed to be shifted out of Delhi are indicated as per annexed. Statement-I. (*See* below)

(c) The details of offices of PSU's (Government Offices which have actually shifted out of Delhi are indicated as per annexed. Statement-II. (*See* below)

(d) and (e) The actual shifting depends upon a number of determining factors like availability of land construction of buildings, etc.

As regards Government Offices the progress with regard to shifting is reviewed from time to time.

As rsgards Public Sector Undertakings the action for shifting is to be initiated by the relevant Administrative Ministries/Departments and the Undertakings and it is a continuous process.